



उच्च शिक्षा में निजी संस्थाओं का योगदान

डॉ. कामना शुक्ला

प्राचीन इतिहास विभाग, कृपालु महिला महाविद्यालय, उत्तर प्रदेश, भारत

Corresponding Email: kamna14shukla@gmail.com

Communicated : 18.06.2026

Revision : 20.07.2026
Accepted : 12.08.2026

Published: 30.09.2026

सारांश :

आज भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली दुनिया की सबसे विशाल और जटिल व्यवस्थाओं में गिनी जाती है। आजादी के बाद एक लंबे समय तक पढ़ाई-लिखाई की पूरी जिम्मेदारी सरकार के पास थी, लेकिन १९९० के दशक में हुए आर्थिक सुधारों ने इस तस्वीर को पूरी तरह बदल दिया। आज जिस तेजी से हमारी जनसंख्या और युवाओं की आकांक्षाएं बढ़ रही हैं, उन्हें देखते हुए निजी शिक्षण संस्थानों की भूमिका बहुत अहम हो गई है। सरकारी संसाधनों की अपनी सीमाओं के बीच, प्राइवेट सेक्टर ने तकनीकी और प्रोफेशनल शिक्षा को घर-घर पहुँचाने में एक जरूरी विकल्प के तौर पर काम किया है। यह शोध पत्र इसी बदलाव को गहराई से समझने की एक कोशिश है। हम इसमें चर्चा करेंगे कि निजी संस्थानों का प्रभाव इतनी तेजी से क्यों बढ़ा, उन्होंने बेहतर सुविधाओं और रोजगार के नए अवसरों के जरिए शिक्षा को कैसे विस्तार दिया, और साथ ही उन चुनौतियों पर भी नजर डालेंगे जो शिक्षा के बढ़ते व्यापारीकरण और गुणवत्ता में अंतर से जुड़ी हैं। अंत में हम यह भी देखेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (छम्च) २०२० के आने के बाद भविष्य में इस क्षेत्र की दिशा क्या होगी

प्रमुख शब्द : उच्च शिक्षा, निजी संस्थान, NEP 2020

प्रस्तावना :

किसी भी देश की तरक्की, उसकी सामाजिक मजबूती और दुनिया के नक्शे पर उसकी साख इस बात पर टिकी होती है कि वहां की उच्च शिक्षा व्यवस्था कितनी दमदार है। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें, तो १९४७ में आजादी के समय भारत की तस्वीर आज से बिल्कुल अलग थी। उस वक्त पूरे देश में सिर्फ २० विश्वविद्यालय और करीब ५०० कॉलेज हुआ करते थे, जिनमें बमुश्किल २ लाख छात्र पढ़ते थे। उस दौर में शिक्षा को पूरी तरह से सरकार की जिम्मेदारी माना जाता था, क्योंकि इसे एक 'जनसेवा' के रूप में देखा जाता था। जैसे-जैसे समय बीता, देश की आबादी बढ़ी और साथ ही बढ़ी युवाओं की बेहतर भविष्य की उम्मीदें। १९८० के दशक तक आते-आते यह साफ हो गया था कि सिर्फ सरकारी खजाने और संसाधनों के दम पर करोड़ों युवाओं को कॉलेज तक पहुँचाना नामुमकिन है। इसके बाद साल १९९१ का दौर आया, जब देश ने 'उदारीकरण और निजीकरण' (LPG reforms) के दरवाजे खोले। इसका सीधा असर शिक्षा के क्षेत्र पर भी पड़ा। सरकार ने अब खुद को इकलौते 'संचालक' के बजाय एक 'मार्गदर्शक' (Facilitator) के रूप में ढालना शुरू कर दिया, जिससे प्राइवेट सेक्टर के लिए रास्ते खुल गए। आज के

आंकड़े चौंकाने वाले और सुखद दोनों हैं। 'अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण' ; षष्ठ की रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारत के लगभग ७८: कॉलेज अब निजी हाथों में हैं और देश के ६०: से ज्यादा छात्र इन्हीं संस्थानों में अपनी डिग्री पूरी कर रहे हैं। आज प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटीज महज एक विकल्प नहीं रह गए हैं, बल्कि वे भारतीय शिक्षा तंत्र की असली बुनियाद बन चुके हैं।

निजी संस्थानों की बढ़ती भूमिका के पीछे के कारण: निजी क्षेत्र के इस उभार के पीछे सबसे बड़ा कारण है बदलता बाजार और आधुनिक जरूरतें। जहां सरकारी संस्थानों पर पुरानी व्यवस्थाओं का बोझ था, वहीं निजी संस्थानों ने तेजी से खुद को बदला। उन्होंने न केवल आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, बल्कि उद्योग की मांग के अनुसार नए-नए कोर्स भी पेश किए। डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डिजिटल मार्केटिंग जैसे विषयों को मुख्यधारा में लाने का श्रेय काफी हद तक इन्हीं प्राइवेट प्लेयर्स को जाता है, जिन्होंने छात्रों को सीधे जॉब मार्केट के लिए तैयार किया।

चुनौतियां और भविष्य की राह: हालांकि, निजीकरण के इस दौर ने कुछ गंभीर सवाल भी खड़े किए हैं। शिक्षा के बढ़ते खर्च ने इसे आम आदमी की पहुँच से दूर

करने का डर पैदा किया है। साथ ही, कुछ संस्थानों में शिक्षा की गुणवत्ता (Quality) को लेकर भी चिंताएं बनी रहती हैं। ऐसे में चुनौती यह है कि हम कैसे विस्तार और गुणवत्ता के बीच संतुलन बिठाएं। आने वाले समय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) २०२० की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर किस तरह एक ऐसी पारदर्शी व्यवस्था बनाते हैं, जहां शिक्षा सिर्फ 'डिग्री बांटने का जरिया' न रहकर वास्तविक ज्ञान और कौशल का केंद्र बने।

भारत में निजी शिक्षण संस्थानों के उभार की असल कहानी: मुख्य कारण

भारत में आज गली-मोहल्लों से लेकर बड़े शहरों तक निजी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की जो बाढ़ दिखाई देती है, वह कोई रातों-रात हुआ चमत्कार नहीं है। इसके पीछे दशकों से बदलते हमारे समाज, अर्थव्यवस्था और युवाओं की बढ़ती उम्मीदों का एक गहरा तालमेल रहा है। आइए समझते हैं कि वे कौन से बड़े बदलाव थे जिन्होंने प्राइवेट सेक्टर के लिए शिक्षा के दरवाजे पूरी तरह खोल दिए।

युवाओं की बढ़ती फौज और 'डिग्री' का सपना (जनसांख्यिकीय लाभांश)

आज भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, जहाँ की आधी से ज्यादा आबादी ३५ साल से कम उम्र की है। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि करोड़ों युवाओं की आँखों में पलते 'बेहतर जीवन' के सपने हैं। हर युवा चाहता है कि वह पढ़-लिखकर एक अच्छी नौकरी पाए और अपनी सामाजिक स्थिति (Social Mobility) को सुधारे। जब लाखों छात्र हर साल स्कूल से निकलकर कॉलेज की ओर बढ़े, तो सरकारी कॉलेजों के बाहर लंबी कतारें लग गईं। सरकारी तंत्र के पास न तो इतने बेंच थे, न इतने कमरे और न ही इतने शिक्षक कि वे इस भारी भीड़ को संभाल सकें। इसी 'गैप' को भरने के लिए निजी संस्थानों ने आगे बढ़कर अपनी जगह बनाई।

सरकारी खजाने की सीमाएं और बजट का 'गैप'

अगर हम इतिहास देखें, तो १९६० के दशक में 'कोठारी आयोग' ने सिफारिश की थी कि देश की जीडीपी (GDP) का कम से कम ६% हिस्सा शिक्षा पर खर्च होना चाहिए। लेकिन कड़वी सच्चाई यह है कि दशकों बीत जाने के बाद भी हम औसतन ३-४% से आगे नहीं बढ़ पाए। जब सरकार के पास नए अस्पताल, सड़कें और बिजली पहुँचाने जैसी बुनियादी चुनौतियों के लिए बजट कम पड़ रहा था, तब नई यूनिवर्सिटीज खड़ी करना एक बड़ी चुनौती बन गया। बजट की इसी कमी ने एक 'खालीपन' (Vacuum) पैदा किया, जिसे भरने के

लिए निजी निवेशकों को आमंत्रित किया गया। सरल शब्दों में कहें तो सरकार ने हाथ खड़े किए, तो प्राइवेट सेक्टर ने कमान संभाल ली।

१९९१ के आर्थिक सुधार और 'कॉर्पोरेट' जगत की मांग
१९९१ के बाद जब भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था के दरवाजे दुनिया के लिए खोले, तो आईटी (IT), बीपीओ (BPO) और मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में नौकरियों की सुनामी आ गई। मल्टीनेशनल कंपनियों को ऐसे पेशेवरों की जरूरत थी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट स्किल्स जानते हों। पुरानी सरकारी यूनिवर्सिटीज का सिलेबस सालों पुराना था और उसे बदलना एक लंबी नौकरशाही प्रक्रिया थी। इसके उलट, प्राइवेट कॉलेजों ने बाजार की नब्ज पकड़ी। उन्होंने तेजी से कंप्यूटर लैब्स बनाई, इंस्ट्रुक्टी के विशेषज्ञों को बुलाया और ऐसे 'जॉब-ओरिएंटेड' कोर्स शुरू किए जो सीधे नौकरी की गारंटी देते थे। यही वजह थी कि युवाओं का रुझान तेजी से निजी इंजीनियरिंग और एमबीए कॉलेजों की तरफ बढ़ा।

मध्यम वर्ग की बढ़ती हैसियत और बच्चों के भविष्य पर निवेश

पिछले तीन दशकों में भारत में एक ऐसा मजबूत मध्यम वर्ग खड़ा हुआ है, जिसकी जेब में पैसा है और दिल में अपने बच्चों को 'सबसे बेहतर' देने की चाहत। आज एक औसत भारतीय माता-पिता अपनी पूरी जमा-पूँजी अपने बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करने को तैयार हैं। वे चाहते हैं कि उनका बच्चा एसी क्लासरूम में पढ़े, फर्स्टेडर अंग्रेजी बोले और उसे कैम्पस प्लेसमेंट मिले। निजी संस्थानों ने इस 'एस्पिरेशनल क्लास' (आकांक्षी वर्ग) की जरूरतों को समझा। चूंकि सरकारी कॉलेजों में सीटें कम थीं और प्रतिस्पर्धा (Competition) बहुत ज्यादा, इसलिए मध्यम वर्ग ने निजी संस्थानों की ऊँची फीस को अपने बच्चों के भविष्य के लिए एक 'सुरक्षित निवेश' मानकर स्वीकार कर लिया।

निष्कर्ष के तौर पर: निजी संस्थानों का उदय केवल मुनाफा कमाने की होड़ नहीं थी, बल्कि यह एक बढ़ते हुए भारत की मजबूरी और जरूरत। दोनों का संगम था। निजी क्षेत्र ने शिक्षा को 'एलीट' (खास लोगों) के दायरे से निकालकर व्यापक स्तर पर फैला दिया है, हालाँकि अब चुनौती इसकी गुणवत्ता और पारदर्शिता को बनाए रखने की है।

भारतीय उच्च शिक्षा में निजी संस्थानों का बड़ा बदलाव: एक बहुआयामी नजरिया

निजी क्षेत्र ने भारत में सिर्फ कॉलेजों की संख्या नहीं बढ़ाई है, बल्कि शिक्षा देने के तरीके और उसकी गुणवत्ता में भी क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। आज अगर

हम शिक्षा के बदलते स्वरूप को देखें, तो निजी संस्थानों के योगदान को इन महत्वपूर्ण बिंदुओं से समझा जा सकता है:

शहरों से कस्बों तक शिक्षा का विस्तार (Infrastructure Expansion)

आज भारत में यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों का जो जाल बिछा है, उसमें निजी क्षेत्र की भूमिका सबसे बड़ी है। भारत में अब ११०० से ज्यादा यूनिवर्सिटी और ४३,००० से अधिक कॉलेज हैं, जिनमें से एक बड़ा हिस्सा प्राइवेट सेक्टर का है। सबसे खास बात यह है कि ये संस्थान अब सिर्फ दिल्ली-मुंबई जैसे बड़े शहरों तक सीमित नहीं हैं। इन्होंने टियर-२ और टियर-३ शहरों (छोटे शहरों और कस्बों) तक पहुँच बनाई है। इससे उन छात्रों को बड़ी राहत मिली है जिन्हें पहले ऊँची शिक्षा के लिए अपना घर छोड़कर दूर जाना पड़ता था। एक तरह से निजी संस्थानों ने उच्च शिक्षा का 'लोकतंत्रीकरण' कर दिया है।

कॉलेज पहुँचने वाले युवाओं की बढ़ती तादाद (GER में उछाल)

सकल नामांकन अनुपात ;**छम्ब्र** यह बताता है कि १८ से २३ साल के कितने युवा वास्तव में कॉलेज पहुँच पा रहे हैं। साल २००१ में यह आंकड़ा सिर्फ ८: के आसपास था, जो आज बढ़कर २८: से ऊपर जा चुका है। इस छलांग के पीछे निजी कॉलेजों की बढ़ती सीटें ही असली वजह रही हैं। अब भारत ने 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२०' के तहत २०३५ तक इस आंकड़े को ५०: तक ले जाने का जो बड़ा सपना देखा है, उसे पूरा करने के लिए निजी क्षेत्र ही हमारी मुख्य ताकत बनेगा।

भविष्य के डिजिटल क्लासरूम और आधुनिक सुविधाएँ

अगर हम कुछ चुनिंदा सरकारी संस्थानों को छोड़ दें, तो बुनियादी सुविधाओं के मामले में कई निजी विश्वविद्यालय आज दुनिया के बेहतरीन संस्थानों को टक्कर दे रहे हैं। उनके पास वातानुकूलित (AC) स्मार्ट क्लासरूम, हाई-टेक लैब्स (जैसे AR/VR लैब), पूरे कैंपस में हाई-स्पीड वाई-फाई और डिजिटल लाइब्रेरी जैसी सुविधाएँ हैं। यह आधुनिक माहौल न केवल छात्रों को पढ़ाई में मदद करता है, बल्कि उन्हें एक वैश्विक स्तर का अनुभव (Global Experience) भी देता है।

प्रोफेशनल कोर्सेज में नई क्रांति (Technical & Medical Hub)

भारत के 'आईटी हब' बनने के पीछे की असली कहानी निजी कॉलेजों में छिपी है। आज देश के ज्यादातर इंजीनियरिंग (B.Tech), मैनेजमेंट (MBA), मेडिकल

और नर्सिंग कॉलेज निजी हाथों में हैं। अगर ये प्राइवेट कॉलेज न होते, तो शायद भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी 'इंजीनियर वर्कफोर्स' नहीं होती। इन्होंने तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा को इतना सुलभ बना दिया है कि आज हर प्रतिभाशाली छात्र अपनी पसंद के करियर को चुन सकता है।

सिलेबस जो 'नौकरी' दिलाए (Job-Oriented Curriculum)

सरकारी यूनिवर्सिटीज में अक्सर पाठ्यक्रम को बदलने में सालों लग जाते हैं, लेकिन निजी संस्थान बाजार की नब्ज पहचानते हैं। वे जानते हैं कि आज इंडस्ट्री को क्या चाहिए। इसीलिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), डेटा साइंस और साइबर सिक्योरिटी जैसे आधुनिक विषयों को सबसे पहले निजी संस्थानों ने ही अपनाया। उनके पास मजबूत 'प्लेसमेंट सेल्स' और उद्योगों के साथ सीधे करार होते हैं, जिससे छात्रों को केवल डिग्री नहीं, बल्कि सीधे करियर बनाने का मौका मिलता है। इंटर्नशिप और गेस्ट लेक्चर्स के जरिए छात्र पढ़ाई के दौरान ही कॉर्पोरेट दुनिया के लिए तैयार हो जाते हैं।

रिसर्च और दुनिया से जुड़ने का मौका (Innovation & Global Tie-ups)

शुरुआत में माना जाता था कि निजी कॉलेज सिर्फ पढ़ाई और डिग्री तक सीमित हैं, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। बिट्स पिलानी, मणिपाल, अशोका और शिव नादर जैसे संस्थान अब रिसर्च और इनोवेशन पर करोड़ों खर्च कर रहे हैं। इनके पास अपने 'इनक्यूबेशन सेंटर' हैं जहाँ छात्र अपने स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। साथ ही, विदेशी यूनिवर्सिटीज के साथ इनके 'एक्सचेंज प्रोग्राम' छात्रों को विदेश जाकर पढ़ने और वैश्विक नजरिया विकसित करने का मौका देते हैं।

निष्कर्ष :

संक्षेप में कहें तो, निजी संस्थानों ने भारतीय उच्च शिक्षा को एक नया आयाम दिया है। उन्होंने शिक्षा को केवल किताबों तक सीमित न रखकर उसे आधुनिक सुविधाओं, नई तकनीक और रोजगार के अवसरों से जोड़ दिया है। आज वे भारतीय शिक्षा तंत्र की 'रीढ़ की हड्डी' बन चुके हैं।

निजी उच्च शिक्षा के सामने खड़ी बड़ी दीवारें: चुनौतियाँ और कड़वी हकीकत

इसमें कोई शक नहीं कि निजी संस्थानों ने शिक्षा का विस्तार किया है, लेकिन इस चमक-धमक के पीछे कुछ ऐसे अंधेरे पहलू भी हैं जो हमारे देश के भविष्य के लिए एक बड़ा सवालिया निशान खड़े करते हैं। आइए, इन चुनौतियों को थोड़ा गहराई से समझते हैं:

जब शिक्षा 'संस्कार' नहीं, 'सौदा' बन गई (Commercialization)

सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार यह साफ किया है कि शिक्षा कोई व्यापार नहीं है, लेकिन हकीकत इसके उलट है। आज कई निजी संस्थानों के लिए छात्र 'सीखने वाले' कम और 'ग्राहक' ज्यादा बन गए हैं। 'कैपिटेशन फीस' (यानी पर्दे के पीछे से लिया जाने वाला डोनेशन) और एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पर वसूले जाने वाले छिपे हुए खर्चों ने पढ़ाई को एक मुनाफा कमाने वाली इंडस्ट्री में बदल दिया है। जब शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ज्ञान के बजाय 'मुनाफा' (Profit) हो जाता है, तो उसकी पवित्रता और गुणवत्ता दोनों खत्म होने लगती हैं

ऊँची फीस और बढ़ता 'अमीर-गरीब' का फासला (Economic Divide)

आज एक औसत भारतीय परिवार के लिए अपने बच्चे को अच्छे निजी कॉलेज में पढ़ाना किसी सपने जैसा हो गया है। इन संस्थानों की फीस इतनी ज्यादा है कि एक मध्यमवर्गीय या गरीब परिवार का मेधावी छात्र वहां पहुँच ही नहीं पाता। नतीजा यह हो रहा है कि देश में दो तरह की शिक्षा व्यवस्था बन गई है: "अमीरों के लिए शानदार प्राइवेट यूनिवर्सिटी और गरीबों के लिए संसाधनों की कमी वाले सरकारी कॉलेज।" यह आर्थिक खाई समाज में एक बड़ा वर्ग-भेद पैदा कर रही है, जहाँ टैलेंट होने के बावजूद पैसे की कमी शिक्षा के रास्ते में रोड़ा बन जाती है।

'डिग्री बांटने वाली दुकानें' और गिरता स्तर

जहाँ कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज वर्ल्ड-क्लास होने का दावा करती हैं, वहीं हजारों छोटे-बड़े कॉलेज ऐसे भी हैं जिन्हें "डिग्री बांटने का कारखाना" कहना गलत नहीं होगा। इन कॉलेजों में न तो ढंग की लाइब्रेरी है, न ही प्रयोगशालाएं (Labs)। वहां से निकलने वाले छात्रों के पास कागजों पर तो डिग्री होती है, लेकिन हाथ में हुनर (Skills) नहीं होता। यही कारण है कि आज देश में डिग्री वाले बेरोजगारों की फौज खड़ी हो रही है, जिन्हें कंपनियां नौकरी देने को तैयार नहीं हैं क्योंकि वे 'जॉब-रेडी' नहीं हैं।

शिक्षकों की अनदेखी और उनका शोषण (Exploitation of Educators)

एक अच्छा संस्थान वही होता है जहाँ शिक्षक खुश और सुरक्षित महसूस करें। लेकिन कई निजी कॉलेज मुनाफा बचाने के चक्कर में शिक्षकों को बहुत कम वेतन (Low Salary) देते हैं और उन्हें कॉन्ट्रैक्ट पर रखते हैं। यूजीसी (UGC) के मानकों को ताक पर रखकर शिक्षकों से मजदूरी कराई जाती है। जब एक शिक्षक को अपनी नौकरी की सुरक्षा और कम वेतन की चिंता

सताएगी, तो वह छात्रों को बेहतर ढंग से पढ़ाने या नई रिसर्च करने में अपना दिल नहीं लगा पाएगा। इसका सीधा नुकसान छात्रों को उठाना पड़ता है।

कागजी नियम और पारदर्शिता का अभाव (Regulatory Loopholes)

यूं तो हमारे देश में यूजीसी (UGC) और एआईसीटीई (AICTE) जैसी बड़ी संस्थाएं नियम बनाने के लिए बैठी हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। निरीक्षण के समय कई कॉलेज "किराए के शिक्षक" (Ghost Faculty) और अस्थायी लैब उपकरण दिखाकर मान्यता हासिल कर लेते हैं। निरीक्षण की प्रक्रिया में भ्रष्टाचार और पारदर्शिता की कमी ने इन फर्जीवाड़ों को और बढ़ावा दिया है। जब तक नियमों को कड़ाई से लागू नहीं किया जाएगा, तब तक ये संस्थान शिक्षा के नाम पर खिलवाड़ करते रहेंगे।

निष्कर्ष के तौर पर: निजी शिक्षा क्षेत्र आज एक ऐसे दोराहे पर खड़ा है जहाँ एक तरफ विकास की अपार संभावनाएं हैं, तो दूसरी तरफ नैतिकता और गुणवत्ता की गहरी खाई। अगर हम भारत को वास्तव में एक 'नॉलेज सुपरपावर' बनाना चाहते हैं, तो हमें शिक्षा को व्यापार से बाहर निकालकर उसे 'अफोर्डेबल' और 'क्वालिटी-ओरिएंटेड' बनाना ही होगा।

उज्ज्वल भविष्य की ओर: राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) २०२० और आगे की राह

निजी शिक्षण संस्थानों की चुनौतियों को देखते हुए अब सरकार और नीति-निर्माता एक ऐसी व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ 'मुनाफाखोरी' कम हो और 'गुणवत्ता' (Quality) ज्यादा। 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२०' इस दिशा में एक बड़ा बदलाव लेकर आई है, जिसका उद्देश्य सरकारी और निजी संस्थानों के बीच के भेदभाव को खत्म करना और एक बेहतर माहौल तैयार करना है। इसके मुख्य बिन्दु कुछ इस तरह हैं:

नियमन का नया अंदाज: "हल्का लेकिन कड़ा" (Light but Tight Regulation)

अक्सर नियम इतने पेचीदा होते हैं कि अच्छे संस्थान भी कागजी कार्रवाई में उलझ जाते हैं, जबकि लापरवाह संस्थान बच निकलते हैं। छम्च २०२० ने 'भ्रष्ट' (भारतीय उच्च शिक्षा परिषद) नाम की एक इकलौती संस्था बनाने का प्रस्ताव दिया है। इसका मंत्र है: "नियम कम, पर निगरानी सख्त।" यानी संस्थानों को काम करने की आजादी तो दी जाएगी, लेकिन उनकी पारदर्शिता और पढ़ाई के स्तर पर सरकार की पैनी नजर रहेगी।

सरकार और निजी क्षेत्र का मेल (PPP Model)

अब वह समय आ गया है जहाँ सरकार और निजी क्षेत्र को एक-दूसरे का विरोधी नहीं, बल्कि 'पार्टनर' बनना होगा। रिसर्च और नए कैंपस बनाने के लिए 'सार्वजनिक-निजी भागीदारी' (PPP) को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे होगा यह कि सरकार के पास जो अनुभव है और निजी क्षेत्र के पास जो आधुनिक संसाधन हैं, वे मिलकर देश के छात्रों के लिए बेहतरीन अवसर पैदा करेंगे।

फीस पर लगाम और सामाजिक जिम्मेदारी (Fair Fee & Scholarships)

फीस को लेकर अक्सर होने वाली मनमानी पर रोक लगाने के लिए एक पारदर्शी सिस्टम की जरूरत है। नए नियमों के तहत कोशिश यह है कि निजी कॉलेज अपनी मर्जी से फीस न बढ़ाएं। साथ ही, 'क्रॉस-सब्सिडी' (Cross-Subsidization) के जरिए यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि निजी संस्थान अपनी कमाई का एक हिस्सा गरीब और जरूरतमंद छात्रों की स्कॉलरशिप पर खर्च करें। इसका सीधा मतलब है पैसे की कमी किसी भी मेधावी छात्र के सपने के बीच नहीं आनी चाहिए।

क्वालिटी की रेटिंग अनिवार्य (Mandatory Accreditation)

जिस तरह हम कोई सामान खरीदने से पहले उसकी रेटिंग देखते हैं, ठीक वैसे ही हर निजी कॉलेज के लिए NAAC या 'NBA' जैसी संस्थाओं से अपनी गुणवत्ता की जांच कराना अनिवार्य होगा। यह पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होगी, जिससे छात्रों और माता-पिता को यह पता चल सके कि किस कॉलेज में पढ़ाई का स्तर कैसा है। इससे 'डिग्री बांटने वाली दुकानों' पर ताला लगेगा और केवल अच्छे संस्थान ही टिक पाएंगे।

निष्कर्ष के तौर पर: NEP २०२० का नजरिया साफ है। हमें ऐसे निजी संस्थानों की जरूरत है जो केवल ऊंची इमारतें ही न खड़ी करें, बल्कि राष्ट्र निर्माण में अपना ईमानदार योगदान दें। भविष्य की राह इसी बात पर टिकी है कि हम कैसे तकनीक और नैतिकता के बीच एक सही तालमेल बिठाते हैं ताकि भारत फिर से 'विश्व गुरु' बनने की दिशा में कदम बढ़ा सके।

निष्कर्ष :**एक बेहतर और संतुलित भविष्य की उम्मीद**

कुल मिलाकर देखा जाए तो, भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था आज जिस विशाल मुकाम पर खड़ी है, उसे वहां तक पहुँचाने में निजी संस्थानों की भूमिका ऐतिहासिक रही है। यह कहना गलत नहीं होगा कि आज वे हमारे शिक्षा तंत्र की 'रीढ़ की हड्डी' बन चुके हैं। उन्होंने न केवल उन दूर-दराज के इलाकों में

कॉलेज पहुँचाए जहाँ सरकारी तंत्र नहीं पहुँच पाया था, बल्कि भारतीय क्लासरूम को आधुनिक तकनीक, नए जमाने के कोर्स और वैश्विक मानकों (Global Standard) से जोड़ने का काम भी किया है।

लेकिन, इस चमक-धमक के बीच कुछ कड़वी हकीकतें भी हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। शिक्षा का बढ़ता खर्च, पढ़ाई के गिरते स्तर और अमीर-गरीब के बीच बढ़ती खाई आज भी हमारे सामने एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ी है। हमें यह समझना होगा कि शिक्षा कोई साधारण 'बाजारू सामान' नहीं है जिसे पूरी तरह मुनाफे और बाजार के भरोसे छोड़ दिया जाए। यह राष्ट्र के निर्माण की नींव है।

भविष्य की राह इसी में है कि सरकार एक 'सख्त और निष्पक्ष मार्गदर्शक' की भूमिका निभाए। हमें एक ऐसी व्यवस्था चाहिए जो ईमानदारी से शिक्षा देने वाले निजी संस्थानों का उत्साह बढ़ाए, लेकिन जो लोग इसे सिर्फ 'डिग्री बेचने का व्यापार' समझते हैं, उन पर कड़ी लगाम कसे। जब हम तकनीक, आधुनिकता और नैतिकता के बीच एक सही संतुलन बिठा लेंगे, तभी भारत वास्तव में एक 'वैश्विक ज्ञान महाशक्ति' के रूप में अपनी पहचान बना पाएगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :

मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। (वेरीअस एयर्स)। ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन (AISHE) रिपोर्ट्स। न्यू दिल्ली।

अग्रवाल, पी. (२००९)। इंडियन हायर एजुकेशन: एनविजनिंग द फ्यूचर। सेज पब्लिकेशन्स।

वर्गीज, एन. वी. एवं पनिग्रही, जे. (२०२१)। इंडिया हायर एजुकेशन रिपोर्ट: प्राइवेट हायर एजुकेशन। रूटलेज इंडिया।

मिश्रा, पी. एवं वशिष्ठ, ए. (२०१७)। ए स्टडी ऑन प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन हायर एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। इंटरनेशनल एजुकेशन एंड रिसर्च जर्नल।

मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट (MHRD)। (२०२०)। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी २०२०। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

तिवारी, आर., अंजुम, बी., एवं खुराना, ए. (२०१३)। रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन इंडियन हायर एजुकेशन। गैलेक्सी इंटरनेशनल इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च जर्नल।

राठौर, एस. सी. (२०२३)। द इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइवेटाइजेशन इन हायर एजुकेशन। सोशल साइंस जर्नल फॉर एडवांस्ड रिसर्च।

मैती, ए. एवं जाना, एस. (२०२५)। प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट इन हायर एजुकेशन इन इंडिया: ए स्टेट लेवल एनालिसिस। कुनाल बुक्स, न्यू दिल्ली।

आल्टबैक, पी. जी. (२०१४)। द इमर्जेस ऑफ ए प्राइवेट हायर एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। इंटरनेशनल हायर एजुकेशन, (७५), १४. १५।

कपूर, डी. एवं मेहता, पी. बी. (२००४)। इंडियन हायर एजुकेशन रिफॉर्म: फ्रॉम हाफ-बैकड

सोशललिज्म टू हाफ-बैकड कैपिटलिज्म। ब्क वर्किंग पेपर नं. १०८, सेंटर फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी।

भूषण, एस. (२००९)। रिस्ट्रक्चरिंग हायर एजुकेशन इन इंडिया। हायर एजुकेशन इन द वर्ल्ड ३, ग्लोबल यूनिवर्सिटी नेटवर्क फॉर इनोवेशन (GUNI)।